प्रश्न: "भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक।" इस कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

परिचय:

प्रसिद्ध संविधानविद् **के.सी. व्हेयर (K.C. Wheare)** ने भारतीय संविधान को **'अर्ध-संघीय' (Quasi-federal)** कहा है। इसका अर्थ यह है कि हमारे संविधान में एक ओर 'संघीय' (Federal) लक्षण मौजूद हैं, जो राज्यों को स्वायत्तता देते हैं, वहीं दूसरी ओर 'एकात्मक' (Unitary) लक्षण भी हैं, जो केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तिशाली बनाते हैं। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने इस विशेष मिश्रण को अपनाया।

1. प्रकृति में संघीय लक्षण (Federal in Form)

संविधान के वे प्रावधान जो इसे एक संघीय ढांचा (जैसे अमेरिका का संविधान) प्रदान करते हैं:

- **दोहरी सरकार (Dual Polity):** भारत में केंद्र और राज्यों के स्तर पर अलग-अलग सरकारें हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करती हैं।
- **शक्तियों का विभाजन (Division of Powers):** संविधान की **7वीं अनुसूची** के माध्यम से शक्तियों को तीन सूचियों (संघ, राज्य और समवर्ती) में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है।
- **संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution):** केंद्र या राज्य, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है।
- **स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary):** केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र और सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करता है।
- **लिखित संविधान (Written Constitution):** भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है, जिससे शक्तियों के बंटवारे में स्पष्टता रहती है।

2. भावना में एकात्मक लक्षण (Unitary in Spirit)

संविधान के वे प्रावधान जो झुकते हुए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, विशेषकर संकट के समय:

- **मजबूत केंद्र (Strong Center):** संघ सूची में अधिक महत्वपूर्ण विषय (जैसे रक्षा,

विदेश नीति) शामिल हैं। साथ ही, **अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers)** भी केंद्र के पास हैं।

- **एकल नागरिकता (Single Citizenship):** अमेरिका के विपरीत, भारत में केवल देश की नागरिकता होती है, राज्यों की नहीं। यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है।
- **आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions):** अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत, आपातकाल के दौरान भारत का ढांचा पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor):** राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति (केंद्र) द्वारा की जाती है, जो राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण का एक जरिया है।
- **अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services):** IAS और IPS अधिकारियों का चयन केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन वे राज्यों में प्रशासन चलाते हैं, जिससे केंद्र का प्रभाव बना रहता है।
- **संसद की शक्ति (Article 3):** संसद किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है या नया राज्य बना सकती है, इसमें राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है।

3. इस 'मिश्रित प्रकृति' का कारण

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, भारतीय संविधान को एक "कठोर संघीय ढांचे" में नहीं ढाला गया है। इसके पीछे मुख्य कारण थे:

1. **राष्ट्रीय एकता:** देश के विभाजन के बाद केंद्र का मजबूत होना आवश्यक था।
2. **विविधता:** भारत की विशालता और क्षेत्रीय विविधताओं के बीच सामंजस्य बिठाना।
3. **विकास:** पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः, यह कहना उचित है कि भारतीय संविधान **"प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक"** है। यह न तो पूरी तरह से अमेरिकी संघवाद की तरह है और न ही ब्रिटिश एकात्मक प्रणाली की तरह। यह एक अनूठा 'सहयोगी संघवाद' (Cooperative Federalism) है, जो सामान्य समय में राज्यों को आजादी देता है लेकिन संकट के समय एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हो जाता है।

Question: "The Indian Constitution is federal in nature but unitary in spirit." Discuss this statement.

Answer:

Introduction:

The famous constitutional expert, **K.C. Wheare**, described the Indian Constitution as **'Quasi-federal'**. This means that our Constitution possesses 'Federal' characteristics on one hand, which grant autonomy to the states, and 'Unitary' characteristics on the other, which make the central government excessively powerful. The framers of the Constitution adopted this unique blend to maintain the unity and integrity of India.

1. Federal Characteristics (Federal in Form)

The provisions of the Constitution that give it a federal structure (like the US Constitution) are:

- **Dual Polity:** India has separate governments at the central and state levels, which function in their respective domains.
- **Division of Powers:** Powers are clearly divided into three lists (Union, State, and Concurrent) through the **7th Schedule** of the Constitution.
- **Supremacy of the Constitution:** No government, central or state, is above the Constitution.
- **Independent Judiciary:** The Supreme Court acts as an independent and supreme body to resolve disputes between the center and the states.
- **Written Constitution:** India's Constitution is written and detailed, ensuring clarity in the distribution of powers.

2. Unitary Characteristics (Unitary in Spirit)

The provisions of the Constitution that make the center more powerful,

especially in times of crisis:

- **Strong Center:** The Union List includes more important subjects (like defense, foreign policy). Additionally, **Residuary Powers** also lie with the center.
- **Single Citizenship:** Unlike the US, in India, there is only national citizenship, not state citizenship. This promotes national unity.
- **Emergency Provisions:** Under Articles 352, 356, and 360, the structure of India becomes completely unitary during an emergency.
- **Appointment of Governor:** Governors of the states are appointed by the President (Centre), which is a means of central control over the states.
- **All India Services:** IAS and IPS officers are selected by the center, but they administer in the states, maintaining the influence of the center.
- **Power of Parliament (Article 3):** Parliament can change the boundaries of any state or create a new state, and the consent of the states is not mandatory in this.

3. The Reason for This 'Mixed Nature'

According to Dr. B.R. Ambedkar, the Indian Constitution was not molded into a "rigid federal framework." The main reasons behind this were:

1. **National Unity:** A strong center was necessary after the partition of the country.
2. **Diversity:** To bring harmony between India's vastness and regional diversities.
3. **Development:** The role of the center was important for the balanced development of backward areas.

Conclusion:

In conclusion, it is appropriate to say that the Indian Constitution is **"federal in nature but unitary in spirit."** It is neither entirely like the

American federalism nor the British unitary system. It is a unique 'Cooperative Federalism' that grants freedom to the states in normal times but unites as one nation during a crisis.